

प्रेषक,

ओम प्रकाश,

सचिव

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 04 सितम्बर 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय में प्राविधानित विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि की धनराशि निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 505/पं.-2/लेखा/क्षे.पं.वि.नि./2009-10 दिनांक 01 अगस्त 2009 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय में विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रुपये 8,66,38,000-00 (रुपये आठ करोड़ छियासठ लाख अठतीस हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार फांट अपने स्तर से किया जाय।

2. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

3. निर्माण कार्य एवं सामग्री कय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय।

4. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की कार्यवाही प्रारम्भ होने के उपरान्त संकलित सूचना प्रपत्र-बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

5. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2003 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का यथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जाय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अंश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि का इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ योजनाओं पर ही व्यय किया जाय।

7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो निर्माण कार्य आरम्भ हो चुके हैं वे यथाशीघ्र पूर्ण किये जायें। इस प्रकार स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर वित्त/नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

8. प्रश्नगत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 409/XII/05/36(10)/05 दिनांक 13 जून 2005 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-515(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28.7.2009 के अनुसार व्यय किया जाय।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम - आयोजनागत - 101 - पंचायतीराज-07-विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि-42-अन्य व्यय की मद से रुपये 3,20,13,000-00 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख तेरह हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101- पंचायतीराज-02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0201-विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना-42-अन्य व्यय की मद से रुपये 4,51,25,000-00 (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र) व अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-03-विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि -42-अन्य व्यय की मद से रुपये 95,00,000-00 (रुपये पितानब्बे लाख मात्र) के नामे आला जायेगा।

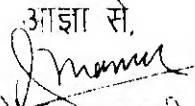
10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 82(P)/XXVII --4/09 दिनांक 02 सितम्बर, 2009 में दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय  
/ (ओम प्रकाश)  
सचिव।

संख्या 492(1)/XII/09/86(10)/2005 टी0सी0-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे. सी. शर्मा)  
अनु सचिव।